Conversion of Loan into equity in various blue chip companies

*400. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to convert loans into equity in various blue chip companies;

(b) whether any financial institution has made such a proposal to Government in 1994-95; and

(c) if so, the names of such financial institutions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) Presumably, the Hon'ble Member is referring to conversion of term loans into equity by financial institutions FIs). Pursuant to Government's statement on Industrial Policy, FIs had been advised in August 1991 to discontinue insertion of the mandatory convertibility clause in loan agreements prospectively for new projects or for expansion of capacities of projects. It was also decided that even in respect of loan agreements executed before August 1991, where conversion had been stipulated but had not yet been exercised, conversion could be waived by the FIs subject to borrower agreeing to pay the prevailing higher rates of interest.

Government have not received any proposal from FIs in this regard during 1994-95.

पर्यटन के विकास हेतु वित्तीय सहायता

4294. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पर्यटन के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) उन परियोजनाओं/ऐतिहासिक स्थानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये यह सहायता प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जो मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं ; और

(घ) 1994–95 और 1995–96 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के पास वित्तीय सहायता की मंजूरी हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिये वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान 69.49 लाख रु की लागत की सात परियोजनायें/स्कीमें स्वीकृत की हैं । स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों के स्थानों के नाम, स्वीकृत राशि तथा वर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र.स.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रु० (लाखों में)
	1992–93	
1.	मांडु में पर्यटन कुटीरें	21.43
2.	उज्जैन में तीर्थ शैड़ तथा जन-सुविधायें	4.66
3.	गौहर महल, भोपाल की प्रकाश पुंज व्यवस्था	4.98
4.	मेले और उत्सव 1993–94	8.00
5.	ओरछा में पर्यटन परिसर	21.07
6.	ओरछा के लिये तम्बुओं की खरीद	2.85
7.	प्रचार सहायता	6.50
	जोड़	69.49

(ग) उज्जन, मांडु, ओरछा और भोपाल, मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में नहीं आते हैं ।

(घ) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में मेलों और उत्सवों का आयोजन करने के लिये वर्ष 1994–95 के दौरान 6.05 लाख रु० की राशि स्वीकृत की है । वर्ष 1995–96 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Discontinuance of Vayudoot Services in Gujarat

4295. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Vayudoot Services have been discontinued at many air-strips in Gujarat in the recent period;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether the State Government have offered to provide land for development and expansion of the airsteps as well as to share expenditure to be incurred thereon for the resumption on these services;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what is the present status in regard to the resumption of Vayudoot Services from these airstrips in the State?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) Yes, Sir. Vayudoot services in Gujarat have been discontinued on account of commercial and operational constraints.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise;

(e) Vayudoot has not immediate plans to resume services in Gujarat.

निजी क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण

4296. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निजी क्षेत्र में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्तावित विमानपत्तन का निर्माण किस राज्य में किया जायेगा;

(घ) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार ने इस प्रस्तावित विमानपत्तन के लिये सभी सुविधायें प्रदान करने की पेशकश की है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य के बंगलौर शहर में किसी निजी पार्टियों के सहयोग से तथा केरल के कोचीन शहर में अनिवासी भारतीयों एवं जनता से एकत्र की जाने वाली धनराशि से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन बनाने हेतु अपनी "अनापत्ति" दे दी है । संबंधित राज्य सरकारों की परियोजनाओं एवं अन्य निश्चित कार्यों की लागत तय करनी है । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी सहायता देगा । इस अवस्था